

रजिस्टर्ड नं० BB/13/SML/2004.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2004/29 अग्रहायण, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 20 दिसम्बर, 2004

संख्या वि०प्र०-विधान-गवर्नमेंट बिल/1-58/2004. — हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य
संवाला विन्यास, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय, फोर्स (संशोधन) विनियम, 2004

2915-राजपत्र/2004-20-12-2004—1,419.

(2795)

मूल्य : 1 रुपया।

(2004 का विधेयक संख्यांक-16) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजूटा,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 26 अक्तूबर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

* 1968 का 8

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 42 का प्रतिस्थापन।

“42. फीसों में वृद्धि करने, कमी करने, परिहार करने या प्रतिदाय करने की शक्ति.—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में उपबन्धित या अधिनियम से संलग्न प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त फीसों में या उनमें से किसी में वृद्धि कर सकेगी, कमी कर सकेगी, परिहार कर सकेगी या प्रतिदाय कर सकेगी; या अन्यथा तथाकथित अनुसूचियों में संशोधन कर सकेगी और उसी रीति में ऐसी अधिसूचना को विखण्डित या संशोधित कर सकेगी।”

3. (1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

2004 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्याख्या।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कारवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) के उपबन्धों के अधीन न्यायालय फीसों में वृद्धि करने और प्रतिदाय करने का उपबन्ध नहीं है। धारा 42 में उपर्युक्त अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में वर्णित समस्त फीसों या उनमें से किसी को कम करने या परिहार करने का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्टाम्प डिपो, नासिक ने वर्ष 1999 में 40 (पैसे) तक की गैर-पोस्टल स्टाम्पों और 55 (पैसे), 60 (पैसे), 75 (पैसे), 90 (पैसे), 1.10 रुपये, 1.25 रुपये, 1.50 रुपये, 3/- रुपये और 4/- रुपये की आसजक न्यायालय फीस स्टाम्पों के विषम वर्ग (ग्रॉड डिनोमिनेशन) का मुद्रण बन्द कर दिया है।

कुमारी सुनीता शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में न्यायालय फीस स्टाम्पों की कमी के विरुद्ध सी० डब्ल्यू० पी० संख्या—1041/2001 दाखिल की है। इसके अतिरिक्त भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी० डब्ल्यू० पी० संख्या 1022/89 नामतः “ऑल इण्डिया जजिज ऐसोसिएशन एण्ड अदार्ज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदार्ज” में अपने निर्णय में राज्यों को न्यायालय फीस में वृद्धि करने की सलाह भी दी है। इसके अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 12-9-1998 को हुई बैठक में यह संकल्प पारित किया है कि लोक अदालतों के माध्यम से पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा निष्पादित वादों में संस्थित फीस/न्यायालय फीस के भाग का न्यायालय द्वारा वादी को प्रतिदाय किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के उपबन्धों में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायालय फीस को कम करने या परिहार करने का प्रावधान है। तथापि उक्त अधिनियम राज्य सरकार को, उक्त अधिनियम में उपबन्धित या उसकी प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस में वृद्धि करने, कमी करने, परिहार करने या प्रतिदाय करने के लिए सशक्त नहीं करता है तथा अधिनियम की उक्त अनुसूचियों में संशोधन करने के लिए भी सशक्त नहीं करता है। इसलिए अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) का संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्यांक 4) 25 अक्तूबर, 2004 को प्रख्यापित किया जिसे राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में 26 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशित किया गया। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को आंशिक उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

सत महाजन,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड (2) राज्य सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम में उपबन्धित या अधिनियम से संलग्न प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीसों में वृद्धि करने, कमी करने, परिहार करने या प्रतिदाय करने के लिए तथा तथाकथित अनुसूचियों को अधिसूचना द्वारा संशोधित करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) का संशोधन और करने के लिए विधेयक ।

सत महाजन,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT)

Bill No. 16 of 2004

**THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT)
BILL, 2004**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

▲

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Act, 2004.

Short title
and com-
mencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 26th day of October, 2004.

1968. 2. For section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following shall be substituted, namely :—

Substitution
of section 42.

“42. *Power to enhance, reduce, remit or refund fees.*—The State Government may, by notification in the Official Gazette, enhance, reduce, remit or refund, all or any of the fees provided in this Act or specified in the First and Second Schedules appended to the Act; or otherwise amend the said Schedules and may in the like manner rescind or amend such notification.”

3. (1) The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

Repeal of
Ordinance
No. 4 of 2004
and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present under the provisions of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968), there is no provision for the enhancement and refund of the court fees. Section 42 provides for reduction or remission of all or any of the fees mentioned in the First and Second Schedules to the Act *ibid*. Further the Central Stamps Depot, Nasik has discontinued the printing of Non-Postal Stamps upto 40(P), and odd denominations of Adhesive Court Fees Stamps of 55(P), 60(P), 75(P), 90(P), Rs. 1.10, 1.25, 1.50 Rs. 3/- and 4/- in the year 1999.

One Ms. Sunita Sharma has filed a C. W. P. No. 1041/2001 in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh against the shortage of Court Fees Stamps. Further the Hon'ble Supreme Court of India in CWP No. 1022/89 titled "All India Judges Association and ors. Vs. Union of India and ors." has also suggested in its judgement that States may consider revising the court fee. Further the State Legal Services Authorities in its meeting held on 12-9-1998 resolved that the part of Institution fee/court fee should be refunded to the plaintiff by the court in the suits disposed of by amicable settlement between the parties through Lok Adalats. The provisions of section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 provides for reduction or remittance of court fee by notification in the Official Gazette. The Act *ibid* however, does not empower the State Government to enhance, reduce, remit or refund any of the fees provided in the Act or specified in the First and Second Schedules thereof, and also does not empower to amend said Schedules of the Act. Thus in order to achieve the desired objectives, it was decided to amend the Act *ibid* immediately.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (8 of 1968) had to be amended urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2004 (Ordinance No. 4 of 2004) on the 25th day of October, 2004 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 26th day of October, 2004. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with minor modifications.

SAT MAHAJAN,
Minister-in-charge.

SHIMLA.

Dated....., 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (2) of the Bill empowers the State Government to enhance, reduce, remit or refund the fees provided in the Act or specified in First and Second Schedules to the Act, and to amend the said Schedules by notification. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2004

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

SAT MAHAJAN,
Minister-in-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The.....December, 2004.

